भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1

उत्तर देने की तारीख: 18.11.2019

विद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा

†1. प्रो॰ रीता बहुगुणा जोशीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में कमी वाले क्षेत्रों की
पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पिछड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित उपाय क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड करने के लिए 70 संकेतकों के आधार पर प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) नामक एक मेट्रिक्स डिजाइन किया है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के प्रमुख स्तरों सहित उसकी स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने का एक ऐसा साधन है, जो सुधार के लिए उनके प्रदर्शन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संचालित करते हैं। पीजीआई का प्रयोजन कमियों को पहचानने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना और तद्नुसार सुधारात्मक कार्रवाई के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल शिक्षा प्रणाली प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ हो सके। समयोचित और विशुद्ध डाटा एकत्र करने के लिए, वर्ष 2018-19 में यूडाईस+ (यूडाईस प्लस) नामक एक कार्यशील और दीर्घकालिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) कक्षा 3,5,8 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों की अध्ययन उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2017, सभी 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को शामिल करते हुए, 701 जिलों में कक्षा 3, 5 और 8 स्तर पर बच्चों द्वारा विकसित क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए 13 नवंबर को आयोजित किया गया था और इसमें 1.10 लाख स्कूलों के 22 लाख विद्यार्थियों को शामिल किया गया था। एनएएस (2017) को जिलों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विभिन्न विषयगत क्षेत्रों जैसे भाषाओं, गणित, ईवीएस/विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में रिपोर्टिंग की इकाई के रूप में संचालित किया गया था। सक्षमता आधारित परीक्षा अधिगम निष्कर्षों पर आधारित थी जिन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के केंद्रीय नियमों में शामिल किया गया है। इसी प्रकार, सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में दिनांक 5 फरवरी, 2018 को देशभर में कक्षा 10 के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया गया। 34 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 610 जिलों के 44,304 स्कूलों में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) के 5 विषयगत क्षेत्रों में 1.5 मिलियन विद्यार्थियों के अध्ययन स्तर का मूल्यांकन किया गया।

एनएएस जिला रिपोर्ट कार्डों को जिला स्तर पर अंतरालों का अभिनिर्धारण करने में सहायता करने और भविष्य में सुधार हेतु कार्यनीतियों को तैयार करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। इसके बाद स्कूलों में अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हस्तक्षेप कार्यढांचा विकसित किया गया है और राज्यों के साथ साझा किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित पहलों को शुरू किया है:

(i) अप्रशिक्षित सेवाकालीन प्रारंभिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि को 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) में संशोधन किया गया है। उपर्युक्त संशोधन के अनुसार, सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित सेवाकालीन सभी शिक्षकों के पास 31 मार्च, 2019 तक केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अकादमिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) को ओडीएल (मुक्त दूरस्थ अधिगम) के माध्यम से इस प्रशिक्षण को आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। ऑनलाइन डी.ईएल.ईडी पाठ्यक्रम 3 अक्टूबर 2017 से शुरू हुआ है। 13 लाख से भी अधिक शिक्षक इन पाठ्यक्रमों में शामिल हुए हैं और इनमें से 10.6 लाख शिक्षकों ने इसे उत्तीर्ण कर लिया है।

(ii) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 01 अप्रैल 2018 से स्कूल शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना- **समग्र शिक्षा** शुरू की है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा की पूर्व तीन केंद्रीकृत प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया है। नई एकीकृत योजना में स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सातत्य के रूप में स्कूल शिक्षा की परिकल्पना गई है और इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना, छात्रों के अधिगम परिणामों को बढ़ावा देना, स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतरालों को पाटना, स्कूलों में अपेक्षित अवसंरचना सुनिश्चित करना, आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता प्रदान करना और शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना है।

(iii) ई-पाठशाला: पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो, वीडियो, पत्र-पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित और गैर-मुद्रित सामग्रियों सहित एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों और विभिन्न अन्य संसाधनों के साथ सभी शिक्षण संसाधनों के प्रसार और प्रदर्शन हेतु ई-संसाधनों की एक एकल रिपोजिटरी विकसित की गयी है।

(iv) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 9 जुलाई 2017 को एक व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओसी) मंच शुरू किया है, जिसे आम तौर पर स्वयम (स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्पायरिंग माइंड्स) कहा जाता है। यह पोर्टल स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है।

(v) 32 राष्ट्रीय चैनलों अर्थात स्वयं प्रभा डीटीएच-टीवी के माध्यम से शैक्षिक ई-विषयवस्तु के अंतरण के लिए सैटेलाइट संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी)-एनसीईआरटी डीटीएच टीवी चैनल अर्थात किशोर मंच (#31) के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है और 9 जुलाई, 2018 से 24x7 शैक्षिक टीवी चैनल शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनआईओएस माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के शिक्षकों और संकेत भाषा हेतु 5 चैनल चला रहा है।

(vi) छात्रों के लिए अनुपूरक शिक्षा सामग्री प्रदान करने और शिक्षकों के कौशल के उन्नयन की दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समर्पित ज्ञान शेयरिंग डिजिटल अवसंरचना प्लेटफॉर्म (दीक्षा) विकसित किया है। इस पोर्टल पर छात्र और शिक्षक दोनों के लिए मंत्रालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त ई-शिक्षा सामग्री अपलोड की जा रही है।

(vii) अगस्त, 2019 में देश भर के 42 लाख शिक्षकों को मुख्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्रधानाचार्यों के क्षमता निर्माण हेतु एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति हेतु

राष्ट्रीय पहल) का शुभारंभ किया गया था। इस प्रशिक्षण का लक्ष्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और उसे बढ़ावा देना, विभिन्न परिस्थितियों से जूझने और प्रथम स्तर पर परामर्शदाता केरूप में कार्य करने में शिक्षकों को प्रेरित करना और समर्थ बनाना है।

(viii) भारत सरकार ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा 2021 में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पीआईएसए) में भाग लेने का निर्णय लिया है। पीआईएसए प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्यांकन है, जोकि विषय वस्तु आधारित मूल्यांकन से अलग इस बात का मूल्यांकन करता है कि छात्रों ने मुख्य क्षमताएं प्राप्त की हैं अथवा नहीं जोकि आधुनिक समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक हैं।

*****